राग दरबारी

असल मुद्दों से भटकाना कोई इनसे सीखे

भारत का प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाता है और उस देश के प्रधानमंत्री को चाकलेट का पैकेट गिफ्ट करता है तो पूरे भारत में तूफान आ जाता है...देश के लोग अपनी सारी समस्याएं भूल जाते हैं...उन्हें याद नहीं रहता कि आज नल नहीं आये...घर में पीने को भी पानी नहीं बचा...वे भूल जाते हैं कि गैस और पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं... वे भूल जाते हैं कि घर में सिर्फ इतना ही राशन बचा है कि आज का खाना बन जाये.. उनके घर की फुटपाथ पर आज पड़ौसी की कार पार्क हो गई तो वो लड़ना भी भूल जाते हैं...सब कुछ भूलकर मेलोडी और मेलोनी के मायाजाल में उलझकर वे अपनी सुधबुध खो बैठे...ये जादू नहीं तो और क्या है...गम भुलाने के लिए ये वो नशा है जो मुफ्त में मिल रहा है...वाह मोदीजी...आपकी एक चॉकलेट के बदले में इटली से आपको जो मिलेगा उसकी तुलना में देश के लोगों का फायदा गिनने के लिए कोई भी आंकड़ा कम है।

देश में मंहगाई चरम सीमा पर है, देश में बेरोजगारी की स्थिति सुरसा की तरह बढ़ती जा रही है, देश भ्रष्टाचार के दलदल में निरंतर फंसता जा रहा है, देश की कृषि,पर्यावरण से लेकर न्याय तक की व्यवस्थाएं चरमरा रही है। ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो आज से नहीं देश की आजादी के बाद से ही यथावत चले आ रहे हैं..बस इनका पैमाना कम ज्यादा होता रहता है पर इनकी प्रामाणिकता आंकड़ों से ही पता चल जाती है , सत्तापक्ष भी इन आंकड़ों को पूरी तरह नहीं नकार सकता । इन सब मुद्दों के लिए देश में कोई माहौल नहीं है।

मेरे देश को ये क्या हो गया है। जनता गूंगी हो चुकी है , नेता इन मुद्दों पर अंधों का स्वांग रचे हुए हैं और सत्तापक्ष बहरा। गांधीजी के तीन बंदरों का यही अर्थ शायद देश समझ रहा है।

जिन पर मुद्दे उठाने की जवाबदारी है वे असल मुद्दों को नजरअंदाज कर मात्र एक व्यक्ति की हंसी उड़ाने में और उस व्यक्ति को बदनाम करने में ही सारी ऊर्जा लगा रहे हैं। मजे की बात है कि इस व्यक्ति के बारे में तथाकथित उनको भी पता है कि वे इस आदमी का वे कुछ बिगाड़ नहीं पायेंगे फिर भी लगे हुए हैं ...लगे हुए हैं।

पेट्रोल और गैस की समस्या विश्वव्यापी है, अनेक देश अपने यहां इन उत्पादों के उपयोग पर किफायत बरतने की अपील कर चुके हैं और वहां की जनता इस पर अमल भी करने लगी है...जब हमारे यहां ऐसी अपील होती है तो इन तथाकथित जवाबदारों द्वारा जमीनी हकीकत देखे बगैर अपील का मजाक बनाया जाता है।

सोना कम खरीदने और विदेश यात्राएं टालने की अपील पर भी मजाक समझ से परे है ..सब जानते हैं कि सोने को आयात करने से और विदेश यात्राएं करने से विदेशी मुद्रा भंडार बाहर जाता है , जो देश की आर्थिक स्थिति खराब करता है । क्या देश के नागरिकों की %सामूहिक जिम्मेदारी% नहीं है कि इन बाहरी संकटों से देश की अर्थव्यवस्था को बचाने में योगदान दे। ये बातें तो योगदान की परिभाषा से भी बाहर है, क्योंकि इस योगदान से न तो जनता का कोई खर्च बढ़ेगा (बल्कि बचत ही है) और न ही किसी भी तरह से जनता का कोई नुकसान होगा। यदि इन अपीलों का मजाक बनाया जाता है तो निश्चित ही महंगाई आदि समस्याओं के लिए कुछ हद तक मजाक बनाने वालों की भी जिम्मेदारी मानी जायेगी।

प्राकृतिक खेती और स्वदेशी सामान अपनाने सहित समस्त देशहित की अपीलों पर भी इन कथित जवाबदारों द्वारा पहले अपील करने वाले को ही अपनाने की बात की जाती है। इन अपीलों पर बेहूदे मजाक की हजारों लाखों पोस्ट मीडिया में रातों रात चिपका दी जाती है।

जनहित की बातों को मजाक में उड़ा देना, जनता का असल मुद्दों से ध्यान भटका देना, वास्तविक मुद्दों पर चिंता करने और देश में ही सरकार से सवाल करने के बजाय एक विदेशी पत्रकार के सवाल पर जवाब न देने पर सवाल करने वालों से मेरा सवाल है कि देश की आर्थिक स्थिति, मंहगाई , बेरोजगारी आदि समस्याओं को मुख्य मुद्दा नहीं बनाने के लिए क्या वे देश की सरकार से भी अधिक दोषी नहीं है?

वैसे भी हम सरकार को दोषी कहां मान रहे हैं, हम तो दोष उस बात का दे रहे हैं कि हमारी सरकार ने एक नार्वेजियन पत्रकार के सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? हमारे लिए मुद्दों का कोई महत्व नहीं है..उन मुद्दों पर देश की बिगड़ती दशा का भी हमारे लिए कोई महत्व नहीं है.. हमारे लिए तो बगैर प्रोटोकॉल के भी सवाल का जवाब देना ज्यादा महत्व रखता है क्योंकि हम देश को वास्तविक मुद्दों से भटकाना चाहते हैं।

पी सी राठी (पूर्व अपर कलेक्टर)
165 AF स्कीम नंबर 54 इंदौर 94253 12515

उत्तर प्रदेश 2027 क्या अब मुकाबला सिर्फ भाजपा बनाम सपा रह गया है

उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर दो ध्रुवों में सिमटती दिखाई दे रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन, संसाधन और सत्ता तंत्र है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भाजपा विरोधी राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभर रही है।

बहुजन समाज पार्टी, जो कभी सत्ता की निर्णायक धुरी हुआ करती थी, आज राजनीतिक संघर्ष के दौर में दिखाई देती है। कांग्रेस जमीन पर सीमित होती जा रही है और छोटे क्षेत्रीय दल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में 2027 का विधानसभा चुनाव धीरे-धीरे सीधे भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच का मुकाबला बनता नजर आ रहा है।

बसपा : अस्तित्व बचाने की चुनौती

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक समय ऐसा था जब बिना बसपा के सत्ता की कल्पना अधूरी मानी जाती थी। दलित राजनीति की सबसे मजबूत आवाज कही जाने वाली पार्टी आज वैसी आक्रामकता और ऊर्जा में दिखाई नहीं देती।

बसपा का कोर वोट बैंक अब भी मौजूद है, विशेषकर जाटव समाज में उसका प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन जमीन पर संगठनात्मक सक्रियता कम हुई है। दूसरी ओर दलित वर्ग का एक बड़ा हिस्सा भाजपा की ओर आकर्षित हुआ है, जबकि मुस्लिम मतदाता रणनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी के साथ खड़े दिखाई देते हैं।

यही कारण है कि आज बसपा सत्ता की दावेदार कम और चुनावी समीकरण बिगाड़ने वाली पार्टी अधिक दिखाई देती है। हालांकि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में बसपा को पूरी तरह खत्म मान लेना राजनीतिक भूल होगी।

भाजपा : संगठन, हिंदुत्व और लाभार्थी राजनीति

भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका बूथ स्तर तक फैला संगठन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि, कानून व्यवस्था का मुद्दा, हिंदुत्व की राजनीति और केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित वर्ग भाजपा को लगातार मजबूत आधार प्रदान कर रहा है।

भाजपा ने पिछले कुछ वर्षों में जातीय राजनीति से ऊपर ÷राष्ट्रवाद और लाभार्थी वर्ग÷ की राजनीति को खड़ा करने का प्रयास किया है। मुफ्त राशन, आवास, उज्ज्वला और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने गरीब वर्ग में भाजपा की पकड़ मजबूत की है।

हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई, किसानों की नाराजगी और स्थानीय नेताओं की उपेक्षा जैसे मुद्दे विपक्ष के लिए अवसर बन सकते हैं। लेकिन भाजपा की चुनावी मशीनरी आज भी विपक्ष की तुलना में कहीं अधिक संगठित दिखाई देती है।

समाजवादी पार्टी : पीडीए की नई राजनीति

अखिलेश यादव ने यह समझ लिया है कि केवल यादव+मुस्लिम समीकरण के सहारे भाजपा को रोकना संभव नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी अब ÷पीडीए÷ यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक राजनीति को नए सामाजिक गठबंधन के रूप में प्रस्तुत कर रही है।

समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि भाजपा विरोधी वोट पूरी तरह उसके पक्ष में केंद्रित हो जाए। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद सपा कार्यकर्ताओं में भी नया उत्साह दिखाई दिया है।

अखिलेश यादव अब खुद को केवल क्षेत्रीय नेता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विपक्ष के प्रमुख चेहरे के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि सपा गैर-यादव पिछड़े और दलित वर्ग में गहरी पैठ बनाने में सफल होती है, तो 2027 का चुनाव बेहद दिलचस्प हो सकता है।

कांग्रेस : समर्थन की भूमिका ज्यादा प्रभावी

कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में जनाधार लगातार कमजोर हुआ है। पार्टी के पास बड़े चेहरे तो हैं, लेकिन मजबूत संगठनात्मक ढांचा नहीं दिखाई देता।

ऐसी स्थिति में कांग्रेस यदि अकेले चुनाव लड़ती है, तो भाजपा विरोधी वोटों का विभाजन हो सकता है। इसलिए राजनीतिक रूप से यह अधिक व्यावहारिक माना जा रहा है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन बनाए रखे और सीमित सीटों पर चुनाव लड़े।

लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता का जो प्रयोग हुआ, उसने भाजपा को चुनौती देने की संभावना जरूर दिखाई। इसी कारण सपा और कांग्रेस का साथ आगे भी जारी रहने की संभावना अधिक दिखाई देती है।

छोटे दल : सीट कम, असर बड़ा

उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटे दल हमेशा निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं।

अपना दल – कुर्मी वोट बैंक में प्रभाव

निषाद पार्टी – पूर्वांचल में निषाद समाज को प्रभावित करती है

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी – राजभर वोटों पर असर

राष्ट्रीय लोकदल – पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट राजनीति का अहम चेहरा

एआईएमआईएम – सीमित क्षेत्रों में मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की कोशिश

ये दल भले सत्ता में सीधे निर्णायक न हों, लेकिन कई सीटों पर जीत और हार का अंतर तय कर सकते हैं।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश 2027 का चुनाव केवल सरकार बनाने का चुनाव नहीं होगा, बल्कि यह देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव साबित हो सकता है।

एक तरफ भाजपा हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और लाभार्थी राजनीति के सहारे सत्ता बचाने की कोशिश करेगी, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और पीडीए राजनीति के जरिए सत्ता परिवर्तन का सपना देखेगी।

बसपा अपनी खोई जमीन तलाश रही है, कांग्रेस सहयोगी भूमिका में दिखाई दे रही है और छोटे दल अपनी-अपनी जातीय ताकत बचाने में जुटे हैं।

फिलहाल राजनीतिक तस्वीर यही कहती है कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई सीधी भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सिमटती जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहां आखिरी कुछ महीनों में पूरा राजनीतिक माहौल बदलने की ताकत होती है।

आशीष चंद्रनारायण दुबे
राजनीतिक रणनीतिकार एवं चुनाव विश्लेषक द पॉलिटिकल लैब

मप्र में राज्यसभा चुनाव के लिए बिछने लगी चौसर

पटवारी और सिंघार ने कांग्रेस आलाकमान को सुझाए अपने-अपने फॉर्मूले

इंदौर। मप्र की राजनीति में राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अंदरखाने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इस बीच कांग्रेस में नेतृत्व और संगठन को लेकर चल रही अंदरूनी खींचतान भी खुलकर सामने आने लगी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के अलग-अलग दिल्ली दौरे ने पार्टी के भीतर चल रहे पाँवर गेम की चर्चाओं को और हवा दे दी है।

कांग्रेस को सबसे बड़ा डर इस बात का सता रहा है कि सत्ता में बैठी भाजपा क्रॉस वोटिंग के जरिए उसके हिस्से की संभावित सीट भी छीन सकती है। यही कारण है कि पार्टी नेतृत्व प्रत्याशी चयन से लेकर विधायकों की एकजुटता तक हर पहलू पर सतर्क नजर बनाए हुए है। कुछ दिन पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। इस दौरान प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भी मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार पटवारी ने राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों को लेकर अपना फीडबैक केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा। इसी कड़ी में सोमवार को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी दिल्ली पहुंचे और उन्होंने मल्लिकार्जुन खरगे से करीब एक घंटे तक बंद कमरे में चर्चा की। बताया जा रहा है कि सिंघार ने स्पष्ट रूप से नेतृत्व को आगाह किया कि यदि उम्मीदवार चयन और विधायकों की निगरानी में सावधानी नहीं बरती गई तो भाजपा कांग्रेस की सीट पर भी कब्जा कर सकती है। उन्होंने भाजपा द्वारा कांग्रेस विधायकों से संपर्क साधे जाने की आशंका जताते हुए राज्यसभा सीट बचाने का एक फॉर्मूला भी नेतृत्व के सामने रखा। सूत्रों का कहना है कि सिंघार ने अपने सुझाव लिखित रूप में भी कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपे हैं।

संगठन की कमजोरी पर भी हुई चर्चा

राज्यसभा चुनाव के बहाने कांग्रेस में संगठनात्मक कमजोरी का मुद्दा भी फिर सामने आ गया है। बताया जाता है कि उमंग सिंघार ने राष्ट्रीय नेतृत्व को प्रदेश संगठन की स्थिति पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा बूथ स्तर तक बेहद सक्रिय है और हर जिले में उसका मजबूत नेटवर्क काम कर रहा है, जबकि कांग्रेस अभी भी कई क्षेत्रों में कमजोर स्थिति में है।

सिंघार ने निकाय चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की जरूरत पर जोर देते हुए सुझाव दिया कि जिला और ब्लॉक स्तर पर नए सिरे से सक्रियता बढ़ाई जाए। उन्होंने कुछ जिलों में संगठन की कमजोरी का उल्लेख करते हुए वहां विशेष रणनीति बनाने की आवश्यकता बताई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस के भीतर चल रही यह समानांतर गतिविधियां पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं।

पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि जब प्रदेश नेतृत्व ही अलग-अलग रणनीति के साथ दिल्ली दरबार में पहुंच रहा है, तब कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम की स्थिति बनना स्वाभाविक है। उनका कहना है कि कांग्रेस का यही आंतरिक शक्ति संघर्ष उसे लगातार सत्ता से दूर रखे हुए है।

भाजपा भी साध रही जातीय समीकरण

दूसरी ओर भाजपा ने भी राज्यसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तेज कर दी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक भाजपा इस चुनाव के जरिए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश करेगी। यदि पार्टी स्थानीय नेताओं को राज्यसभा भेजने का फैसला करती है, तो सवर्ण नेताओं को प्राथमिकता मिल सकती है। संभावित नामों में पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष कांतदेव सिंह के अलावा पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा और सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नाम प्रमुखता से चर्चा में हैं।

राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी है कि भाजपा कैलाश विजयवर्गीय को राज्यसभा भेजकर उन्हें एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका दे सकती है। पार्टी उन्हें संसदीय बोर्ड में शामिल करने जैसे विकल्पों पर भी विचार कर सकती है। वहीं डॉ. नरोत्तम मिश्रा के नाम को लेकर भी अटकलें जारी हैं। माना जा रहा है कि यदि वे दतिया की राजनीति से हटकर दिल्ली की भूमिका पसंद करते हैं तो पार्टी उनके नाम पर भी गंभीरता से विचार कर सकती है। भाजपा के सामने जातीय संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी है। वर्तमान में मध्यप्रदेश से भाजपा के राज्यसभा सांसदों में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व पहले से मौजूद है। ऐसे में पार्टी एक सीट पर सवर्ण और दूसरी सीट पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के चेहरे को मौका देने की रणनीति बना सकती है।

सूत्रों का कहना है कि यदि चुनावी गणित ऐसा बना कि भाजपा तीसरी सीट पर भी दांव लगाए, तो वहां भी किसी प्रभावशाली सवर्ण चेहरे को मैदान में उतारा जा सकता है। कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव को लेकर मध्यप्रदेश में राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है और आने वाले दिनों में कांग्रेस तथा भाजपा दोनों में अंदरूनी समीकरण और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।

कार्टून कोना...

recreation

पद और जिम्मेदारी मिली सुविधाएं-अधिकार नदारद!

मंत्री दर्जा ने मिलने से असमंजस में निगम-मंडलों, आयोगों के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष

इंदौर। मप्र में निगम-मंडलों, आयोगों और प्राधिकरणों में लंबे इंतजार के बाद की गई नियुक्तियों ने भाजपा संगठन के भीतर राजनीतिक संतुलन तो साध दिया है, लेकिन अब मंत्री दर्जे को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए गए नेताओं के बीच यह सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है कि उन्हें केवल पद और जिम्मेदारी तक सीमित रखा जाएगा या फिर कैबिनेट एवं राज्यमंत्री स्तर की सुविधाएं और अधिकार भी मिलेंगे।

प्रदेश सरकार ने संगठन के साथ समन्वय बनाकर क्षेत्रीय, सामाजिक और वरिष्ठता के आधार पर अब तक करीब 60 नियुक्तियां की हैं। इनमें 10 प्राधिकरण, 8 निगम, 5 आयोग, 4 बोर्ड, 3 समितियां तथा अन्य संस्थानों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां शामिल हैं। भाजपा ने इन नियुक्तियों के जरिए वरिष्ठ नेताओं के साथ युवा और सक्रिय कार्यकर्ताओं को भी साधने का प्रयास किया है। हालांकि नियुक्तियों के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि इस बार मंत्री दर्जा मिलने के बावजूद सुविधाओं और संसाधनों में कटौती हो सकती है।

इस बार सीमित सुविधाएं-पार्टी सूत्रों का कहना है कि सरकार अशासकीय नियुक्तियों वाले अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री एवं राज्यमंत्री का दर्जा देने पर विचार कर रही है, लेकिन उनसे जुड़ी कई पारंपरिक सुविधाओं को सीमित किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोग इसे वीआईपी संस्कृति कम करने की कोशिश मान रहे हैं, जबकि कई नेताओं का मानना है कि सरकार खर्चों में कटौती का संदेश देना चाहती है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक निगम-मंडलों की नियुक्तियां केवल प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं होतीं, बल्कि संगठन में लंबे समय से सक्रिय कार्यकर्ताओं को सम्मान और जिम्मेदारी देने का माध्यम भी मानी जाती हैं। ऐसे में मंत्री दर्जा इन पदों की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। दिसंबर 2021 में जब निगम-मंडलों में नियुक्तियां हुई थीं, तब अधिकांश पदाधिकारियों को तत्काल कैबिनेट और राज्यमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। इसके बाद उन्हें सरकारी वाहन, बंगला, स्टाफ और प्रोटोकॉल जैसी सुविधाएं भी मिली थीं। मंत्री दर्जा मिलने के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को वेतन, उपचार भत्ता और कार्यालय खर्च के लिए निश्चित राशि मिलती है। इसके अलावा सरकारी वाहन और चालक, हर महीने पेट्रोल-डीजल की तय सीमा, सरकारी आवास, कार्यालय स्टाफ, सुरक्षा गार्ड तथा सरकारी यात्राओं के लिए टीए-डीए जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। कई मामलों में परिवार को भी उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिलता है।

अधिकांश पूर्व पदाधिकारियों को इस बार मौका नहीं-नई सूची की एक और विशेषता यह है कि 2021 में निगम-मंडलों में स्थान पाने वाले अधिकांश नेताओं को इस बार दोबारा मौका नहीं मिला। केवल दो-तीन नाम ही नई सूची में दोहराए गए हैं। कई नेताओं को संगठन में नई जिम्मेदारियां मिल चुकी हैं, जबकि कुछ नेता विधायक और मंत्री बन गए हैं। पूर्व सूची में शामिल शैलेन्द्र बरुआ अब भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। जितेंद्र लिटोरिया को कार्यालय व्यवस्था प्रभारी बनाया गया है, जबकि आशुतोष तिवारी प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जयपाल चावड़ा किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। मंजू दादू और रमेश खटीक विधायक बन चुके हैं, जबकि एंदल सिंह कंसाना मंत्री पद तक पहुंच चुके हैं। वहीं पिछली सूची के कई प्रमुख चेहरे इस बार बाहर हो गए हैं। इनमें इमरती देवी, गिरिजा दण्डोतिया, रणवीर जाटव, मुन्नालाल गोयल, रघुराज कंसाना, जसवंत जाटव, प्रहलाद भारती, नरेन्द्र बिरथरे और राजकुमार कुशवाह जैसे नाम शामिल हैं।

सूत्रों के मुताबिक नियुक्तियों का सिलसिला अभी समाप्त नहीं हुआ है। आने वाले समय में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की कार्यपरिषद, जनभागीदारी समितियों तथा प्रदेश के 16 नगर निगमों में वरिष्ठ पार्षदों की नियुक्तियां भी की जा सकती हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों और सरकारी संस्थानों में भी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां देने की तैयारी चल रही है।